# योजना का सार

## ग्रामीण भारत में WASH का दशक

### परिचय

- पिछले दशक में भारत ने जल, स्वच्छता एवं स्वच्छता व्यवहार (WASH) के क्षेत्र में एक सहज किंतु अत्यंत प्रभावशाली बदलाव देखा है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) व जल जीवन मिशन (JJM) ने तकनीक, ग्राम पंचायतों की भागीदारी और समुदाय-आधारित योजना, क्रियान्वयन एवं निगरानी को केंद्र में रखते हुए ग्रामीण विकास की नई दिशा तय की है। इन पहलों ने स्वास्थ्य, गरिमा, आजीविका, सामाजिक समावेशन और आर्थिक प्रगति पर गहरा प्रभाव डाला है।

### ऐतिहासिक संदर्भ

- भारत की WASH यात्रा का लंबा इतिहास रहा है :
- **प्राचीन काल:** सिंधु घाटी सभ्यता (2500 ई.पू.) में विकसित नगरीय नियोजन, ढंके हुए नाले और घरों में शौचालय मौजूद थे।
- **औपनिवेशिक व स्वतंत्रता पश्चात:** स्वच्छता सार्वजनिक प्राथमिकता नहीं बन सकी और इस क्षेत्र में जाति-आधारित कलंक भी बाधक रहा।
- **1951 के बाद:** प्रथम पंचवर्षीय योजना से स्वास्थ्य, जल व स्वच्छता पर क्रमिक ध्यान दिया गया। इसके तहत सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम (1986), टोटल सैनिटेशन कैंपेन (1999) और निर्मल भारत अभियान (2009) शुरू हुए।

- **ग्रामीण जलापूर्ति:** वर्ष 1954 के राष्ट्रीय जलापूर्ति कार्यक्रम से लेकर स्वजलधारा (2002), NRDWP (2009-10) और NWQSM (2017) तक कई सुधार हुए किंतु समुदाय की भागीदारी व व्यवहार परिवर्तन सीमित रहे।

## *टर्निंग प्वाइंट : 2014 के बाद*

- वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा ODF भारत का लक्ष्य घोषित होने के साथ एक निर्णायक परिवर्तन आरंभ हुआ।

## *स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G)*

- 10 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय निर्माण
- ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 2014 के 39% से बढ़कर 2019 में 100%
- **फेज-II का लक्ष्य :** संपूर्ण स्वच्छता (ODF Plus) ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन (SLWM) पर ज़ोर

## *जल जीवन मिशन (JJM)*

- वर्ष 2019 में हर ग्रामीण घर तक नल से जल (FHTC) का लक्ष्य
- सुरक्षित, पर्याप्त एवं निरंतर पेयजल (त्55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, BIS 10500 मानक) सुनिश्चित करना
- इन पहलों ने WASH दृष्टिकोण को इंफ्रास्ट्रक्चर-केंद्रित से जन-केंद्रित मॉडल में बदल दिया, जहाँ ग्राम पंचायतें और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ (VWSCs) मुख्य भूमिका निभा रही हैं।

## *समुदाय आधारित परिवर्तन*

- ग्राम पंचायतें विलेज एक्शन प्लान (VAP) तैयार कर जल स्रोत, आपूर्ति और ग्रेवॉटर प्रबंधन को समाहित करती हैं।

- VWSCs में 50% से अधिक महिलाएँ हैं और 5.2 लाख से अधिक समितियाँ हैं जो 5.85 लाख गाँवों में गठित हैं।
- महिला SHGs, स्कूली छात्र एवं सेवानिवृत्त कर्मी आदि स्वच्छता व्यवहार, रखरखाव व जल प्रबंधन के अहम भागीदार।

## तकनीकी नवाचार

- **ट्विन-पिट शौचालय :** किफायती, कम-रखरखाव और पर्यावरण-अनुकूल
- **सौर-चालित जल प्रणालियाँ :** बिजली निर्भरता कम
- **लद्दाख में इंसुलेटेड पाइप :** शून्य से नीचे तापमान में जल आपूर्ति
- **गुजरात के फ्लोटिंग वाटर स्कीम :** बाढ़रोधी
- **IoT आधारित निगरानी :** फ्लो मीटर, क्लोरीन एनालाइजर, डिजिटल डैशबोर्ड, शिकायत निवारण

## जल गुणवत्ता निगरानी

- 2,183 प्रयोगशालाएँ और मोबाइल टेस्टिंग वैन
- WQMIS से नागरिक ऑनलाइन जल गुणवत्ता देख सकते हैं।

## व्यवहार परिवर्तन और जन भागीदारी

- IEC अभियानों, जैसे- स्वच्छाग्राही, दरवाजा बंद, जल उत्सव, स्वच्छ सुवजल गाँव, स्वच्छ सुवजल शक्ति सम्मान से जागरूकता बढ़ी।
- महिला-नेतृत्व वाली पहलें, जैसे- जल सखी, जल सहेली, जल सहायिका; जल संरक्षण व सामुदायिक भागीदारी का नेतृत्व करती हैं।
- MGNREGS, NHM और समग्र शिक्षा के साथ कन्वर्जेन्स से संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हुआ।

## स्कूलों एवं आंगनवाड़ियों में WASH

- NEP 2020 और SDGs 4 व 6 के अनुरूप :
- लड़कियों के लिए अलग शौचालय, विकलांग बच्चों के लिए सुगम्य टॉयलेट, सुरक्षित पेयजल
- स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छता पखवाड़ा, सामूहिक हाथ धोने जैसे व्यवहार परिवर्तन अभियान
- वर्षा जल संचयन, ग्रेवॉटर रीयूज, रूफटॉप सिस्टम और किचन गार्डन से स्थायित्व
- UDISE+] PRABANDH पोर्टल, जियो-टैगिंग और डिजिटल डैशबोर्ड से नियमित मॉनिटरिंग

## आगे की दिशा

- विकसित भारत @2047 के संदर्भ में WASH के मुख्य लक्ष्य :
- ODF Plus और स्वच्छ सुवजल गाँवों को संस्थागत SLWM प्रणालियों से सतत बनाए रखना
- सुरक्षित पेयजल की सार्वभौमिक व समान पहुँच, विशेषकर हाशिए के समुदायों तक
- IoT, AI, GIS और मोबाइल आधारित निगरानी से डिजिटल परिवर्तन
- ग्रामीण इंजीनियरों, VWSCs और 'बेयरफुट टेक्नीशियन्स' की क्षमता वृद्धि
- अंतर-विभागीय समन्वय के साथ ग्राम पंचायतों को स्थानीय सेवा प्रदाता के रूप में सशक्त करना

## निष्कर्ष

- विगत दस वर्षों में भारत ने स्वच्छता अभाव से गरिमा, जल संकट से जल सुरक्षा और टॉप-डाउन मॉडल से समुदाय-आधारित प्रशासन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। SBM और JJM ने सिद्ध किया है कि नीति, तकनीक और समुदाय जब एकसाथ आगे बढ़ते हैं तो ग्रामीण जीवन में गहरा परिवर्तन संभव है। WASH क्रांति समावेशी विकास, लैंगिक सशक्तिकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सहभागी लोकतंत्र का मॉडल प्रस्तुत करती है जो अमृत काल में सतत विकास की नींव रखती है।

# लाइट हाउस इनिशिएटिव

## संदर्भ

- भारत की ग्रामीण स्वच्छता यात्रा ने 2014 के बाद से बड़ी प्रगति की है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) ने खुले में शौच से मुक्ति (ODF) दिलाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।
- किन्तु ODF दर्ज होने के बाद भी स्वच्छता को बनाए रखना, ठोस व तरल कचरे का सही प्रबंधन करना तथा स्वच्छता को ग्रामीण शासन का हिस्सा बनाना अब भी एक चुनौती है।

## लाइट हाउस इनिशिएटिव के बारे में

- ग्रामीण स्वच्छता के बदलते परिदृश्य में लाइट हाउस इनिशिएटिव (LHI) का पहला चरण वर्ष 2022 में शुरू हुआ।
- इसे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS)] इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन (ISC) और विभिन्न कॉर्पोरेट साझेदारों ने मिलकर शुरू किया।

- इसका उद्देश्य 75 ग्राम पंचायतों (GPs) को लाइट हाउस GP के रूप में विकसित करना था, जहाँ समुदाय-आधारित और टिकाऊ स्वच्छता मॉडल प्रस्तुत किए जा सकें।

## पहले चरण की उपलब्धियाँ

- **समुदाय-नेतृत्व वाले नवाचार :** आंध्र प्रदेश के नाडिमापालेम गाँव ने कचरा संग्रह के लिए 1 रुपये/दिन उपयोगकर्ता शुल्क लागू किया, जिससे 90% स्रोत-स्तर पर कचरा अलगाव और घरों में कंपोस्टिंग को बढ़ावा मिला।
- **क्षमता निर्माण :** पहले चरण ने दिखाया कि संस्थागत क्षमता, फंडिंग का बेहतर उपयोग और स्थानीय स्तर पर स्वामित्व बेहद ज़रूरी है।
- **मान्यता :** कई ग्राम पंचायतों को टिकाऊ कचरा प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर पुरस्कार मिले।

## दूसरे चरण की ओर बढ़ते हुए

- पहले चरण से मिले अनुभवों के आधार पर दूसरा चरण (जुलाई 2024 से मार्च 2025) शुरू किया गया।
- यह 14 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 37 जिलों के 43 ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है।
- इनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

## दूसरे चरण के उद्देश्य

- सभी के लिए सुरक्षित और समान स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए SDG लक्ष्य 6.2 को समर्थन देना
- ODF प्लस मॉडल ब्लॉक विकसित करना, जिन्हें अन्य स्थानों पर दोहराया जा सके

- कॉर्पोरेट एवं सार्वजनिक क्षेत्र को जोड़कर नवाचार-आधारित विकेंद्रीकृत स्वच्छता समाधान तैयार करना
- ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन (SLWM) के लिए टिकाऊ संचालन व रखरखाव (O&M) मॉडल दिखाना

## कार्यप्रणाली एवं दृष्टिकोण

- **समुदाय आधारित नेतृत्व :** गाँव की जल एवं स्वच्छता समितियाँ (VWSCs)] स्वयं सहायता समूह (SHGs) और स्थानीय नेता योजना व क्रियान्वयन का नेतृत्व करते हैं।
- **डेटा-आधारित निगरानी :** नियमित आकलन, डैशबोर्ड और IEC/BCC अभियान निर्णय लेने में मदद करते हैं।
- **तकनीकी उपयोग :** तकनीकी उपकरण O&M, जल गुणवत्ता और कचरा प्रबंधन को आसान बनाते हैं।
- **वित्तीय मॉडल:** उपयोगकर्ता-शुल्क प्रणाली O&M के लिए आवश्यक धन की निरंतरता सुनिश्चित करती है।

## चुनौतियाँ और अवसर

- योजनाओं के शुरुआती चरण में ही कॉर्पोरेट साझेदारों की भागीदारी से बेहतर तालमेल बनता है।
- समुदाय का स्वामित्व कार्यों की गति, टिकाऊपन और अनुपालन के लिए आवश्यक है।
- समावेशन पर ध्यान : वंचित समूहों, महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।
- तकनीक व निगरानी से स्वच्छता शासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और बड़े पैमाने पर लागू करना आसान होता है।